::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔरकेन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST &CENTRAL EXCISE
द्वितीय तल,जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan
रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road
राजकोट / Rajkot – 360 001
Tele Fax No. 0281 – 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in

सत्यमेव जयते

रजिस्टर्डडाकए.डी.द्वारा

DIN- 20230364SX0000999B38

क	अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक/Date
	GAPPL/COM/STD/194/2022	165/AC/NIS/CGST/BVR-3/2022-23	21-06-2022

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):

BHV-EXCUS-000-APP-106-2023

आदेश का दिनांक / Date of Order: **24.03.2023** जारी करने की तारीख / Date of issue: **27.03.2023**

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by **Shri Shiv Pratap Singh**,Commissioner (Appeals),Rajkot.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर,राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham:

घ अपीलकर्ता&प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of theAppellant&Respondent :-

M/s. Sunilbhai Vallabhbhai Dhamecha, Jaliya, Taluka & Distt. Amreli, Amreli

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है ।/

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to: -

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए ।/

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायप्रधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए । इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग ,ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of dutydemand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना,रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

(i) वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी । /
The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है

(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं॰ 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) **भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन :**
Revision application to Government of India:

इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

(i) यदि माल के किसी नुक्सान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए है।/
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए ।
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशो का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है । / In case, if the order covers various umbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended.

(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं । /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.

:: अपील आदेश / ORDER-IN-APPEAL ::

The Assistant Commissioner, CGST Division-III, Bhavnagar has filed Appeal No.GAPPL/COM/STD/194/2022 on behalf of the Commissioner, Central GST & Central Excise, Bhavnagar (hereinafter referred to as "Appellant-Department") in pursuance of the direction and authorization issued under Section 84 of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'Act') against Order-in-Original No. 165/AC/NIS/CGSTBVR-3/2022-23 dated 21.06.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST Division-3, Bhavnagar (*hereinafter referred to as* 'adjudicating authority') in the case of M/s. Sunilbhai Vallabhbhai Dhamecha, Jaliya (*hereinafter referred to as* 'Respondent').

2. The facts of the case, in brief, are that the Income Tax Department shared the third-party information/ data based on Income Tax Returns/ 26AS for the Financial year 2015-16 & 2016-17 of the Respondent. Letter dated 28.07.2020 was issued by the Jurisdictional Range Superintendent requesting the Respondent to provide information/documents viz. copies of I.T. Returns, Form 26AS, Balance Sheet (including P&L Account), VAT/ Sales Tax Returns, Annual Bank Statement, Contracts/ Agreements entered with the persons to whom services provided etc. for the Financial year 2015-16 & 2016-17. However, no reply was received from the Respondent.

3. In absence of data/ information, a Show Cause Notice dated 21.12.2020 was issued to the Respondent, demanding Service Tax and cess to the tune of Rs. 3,56,296/- under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act') alongwith interest under Section 75 of the Act. It was also proposed to impose penalties under Section 77(1)(a), 77(2), 77(1)(c) and 78 of the Act upon the Respondent.

4. The adjudicating authority vide the impugned order, after analyzing the documentary evidences, dropped the entire proceedings initiated against the Respondent by demanding Service Tax of Rs. 3,56,296/- under Section 73(1) along with interest under Section 75 of the Act, penalty under Section 78 of the Act, penalty under Section 77(1)(c) & 77(2) of the Act.

5. Being aggrieved, the Appellant-Department has preferred the present appeal on various grounds that the Adjudicating Authority found that the Respondent has earned the income on account of 'Mandap Service' provided to Mahanagar Palika (Municipal Corporation), Junagadh for 'Mahashivratri' festival which he found was 'religious ceremony event' and held that the Respondent is eligible for exemption as per Sr. No. 5(b) of Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20.06.2012. It is the contention of the Appellant-Department that the

Adjudicating Authority has failed to appreciate the fact that the Respondent themselves did not conduct any religious ceremony. The civic body i.e. Municipal Corporation arranged religious festival in which the Respondent provided 'mandap' services. The said services do not fall under negative list prescribed under Section 66D of the Act. The services provided by Government or local authority is exempted from the Service Tax by virtue of Sr. No. 1 of Section 66D of the Act. Section 66F of the Act also lays principles for interpretation which states that 'unless otherwise specified, reference to a service (herein referred to as main service) shall not include reference to a service which is used for providing main service'. Hence, it cannot be said that if main service is exempted, all services used for providing main service are exempted. The Respondent did not produce any document to prove that the services provided were exempted from Service Tax and they could not prove that they themselves were conducting religious ceremony. Therefore, services provided by them did not fall under negative list prescribed under Section 66D of the Act. As per Section 66B of the Act provides that there shall be levied a tax to be referred to as Service Tax on the value of all services, other than those services specified in the negative list, provided or agreed to be provided in the taxable territory by one person to another and collected in such a manner as may be prescribed.

6. The Respondent filed Cross Objection on 15.03.2023, *inter alia*, contending that he is engaged in the business of providing Mandap service. During the relevant years, he provided 'Mandap Service' to Mahanagar Palika, Junagadh for 'Mahashivratri' festival, which is covered under 'Religious Ceremony Event'. This activity is fully religious in nature and does not come within the category of social or cultural activity. He relied on Notification No. 14/2003-Service Tax wherein taxable services provided to any person by a mandap keeper for the use of the precincts of a religious place as a mandap, from the Service Tax leviable thereon, under Section 66 of the said Act. He also relied on para 2.7 of Circular No. 59/8/2003-Service Tax dated 20.06.2003 wherein services provided by the religious centres as Mandap Keeper in their precincts have been exempted from Service Tax. The service provided by him is squarely covered under Notification No. 14/2003-Service Tax and he is not liable to pay Service Tax on this exempted receipts. He relied upon case law in the case of (i) Breach Candy Swimming Bath Trust Vs. CCE, Mumbai-I as reported at STO-2006-CESTAT-203 (ii) CCE, Mangalore Vs. Krishnapur Mutt as reported at STO-2003-CESTAT-59 (iii) CCE Vs. Dakshina Kannada Mogaveera Mahajana Sangha as reported at STO-2009-CESTAT-1548. He requested to uphold the impugned order.

7. Personal hearing in the matter was held on 16.03.2023. CA Monica Pedhadiya appeared for personal hearing and submitted that the Mandap Keeper

service provided by them for a religious ceremony is exempted vide Notification No. 14/2003-Service Tax. She also relies upon case law of CCE, Mangalore Vs. Krishnapur Mutt and CCE Vs. Dakshina Kannada Mogaveera Mahajana Sangh as mentioned in their written submissions made in response to the department appeal. She also submitted a copy of ITR, Form 26AS, Balance Sheet, profit & loss account etc. and requested to reject the appeal by the Department.

8. I have carefully gone through the case records, Show Cause Notice, impugned order and appeal memorandum filed by the Appellant-Department. I find that the main issue that is to be decided in the instant case is whether the Mandap Keeper service provided by the Appellant to Mahanagar Palika i.e. Municipal Corporation, Junagadh is exempted or otherwise.

9. It is the contention of the Appellant-Department that the Respondent themselves did not conduct any religious ceremony. The civic body i.e. Municipal Corporation arranged religious festival in which the Respondent provided 'mandap' services. The said services do not fall under negative list prescribed under Section 66D of the Act. The Adjudicating Authority held that the services provided by the Respondent are covered under Sr. No. 5(b) of Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20.06.2012, which is re-produced below for reference:

> *5. Services by a person by way of-*
>
> *"(a) renting of precincts of a religious place meant for general public, owned or managed by an entity registered as a charitable or religious trust under section 12AA of the Income-tax Act, 1961(hereinafter referred to as the Income-tax Act), or a trust or an institution registered under sub clause (v) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act or a body or an authority covered under clause (23BBA) of section 10 of the Income-tax Act;" substituted vide Notification 40/2016- Service Tax. or*
>
> *(b) conduct of any religious ceremony;*

On plain reading of the above provisions, it is clear that the services by a person by way of conduct of any religious ceremony is exempt from Service Tax. Here in the case hand, the Respondent has not conducted any religious ceremony. However, it is also fact that the famous "Maha-Shivratri" Mela of Junagadh is being organized by the civic body of Junagadh every year. Now, it is not the work of the Junagadh Municipal Corporation to arrange for mandap in the "Mahashivratri" mela. Therefore, the municipal corporation has awarded the work to the Respondent. Thus, the services provided by the Appellant is helping the Junagadh Municipal Corporation to conduct the religious ceremony called "Mahashivratri Mela" but Respondent themselves not conducted any religious ceremony. Thus, applying the wordings mentioned in the Notification, the stand taken by the Appellant-Department appears correct.

10. The argument of the Respondent that their service is exempt by way of Notification No. 14/2003-Service Tax dated 20.06.2003 is misplaced since the

said Notification was rescinded vide Notification No. 34/2012-Service Tax dated 20.06.2012 and thus, the same is not applicable in the case on hand. Likewise, the judgements relied upon by the Respondent are of no help to them since the same were for the period prior to 2012, whereas the present case is covering the period 2015-16 & 2016-17.

11. I find that the Adjudicating Authority has not gone into the detailed verification and true spirit of the wordings applied in the Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20.06.2012 which resulted into an appeal by the Appellant-Department. Therefore, I am of considered view that the case should be remanded back to the Adjudicating Authority, who shall call for all the relevant documents and decide the matter in *de novo* by passing speaking order. The Respondent is also directed to provide required information as and when called upon by the adjudicating authority. Needless to mention that Order in de novo proceeding shall be passed by adhering to the principles of natural justice.

12. I set aside the impugned order and dispose of the appeal by way of remand to the adjudicating authority as discussed above.

13. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है ।

13. The appeal filed by Appellant is disposed off as above by way of remand.

सत्यापित / Attested

24-3-23

आर. एस. बोरीचा / R. S. BORICHA
अधीक्षक / Superintendent
के. व. एवं सेवा कर अपील्स, राजकोट
CGST Appeals, Rajkot

(शिव प्रताप सिंह)/(Shiv Pratap Singh)
आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

To, M/s. Sunilbhai Vallabhbhai Dhamecha, At: Jaliya, Taluka & Dist.: Amreli-365610.	सेवा में, मे॰ सुनीलभाई वल्लभभाई धामेचा, गाँव: जालिया, तालुका एवं जिल्ला: अमरेली, पिन:365610 ।

प्रतिलिपि :-

1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर आयुक्तालय, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3) अपर/सयुंक्त आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल-3, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5) गार्ड फ़ाइल।